PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 038
दि. 07.06.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तृणमूल में 'हस्ताक्षर संग्राम': कालीघाट की बैठकों के दस्तावेज लीक होने से बढ़ा सियासी तूफान, पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष खुलकर आया सामने

पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से चल रहा तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जिसने पार्टी नेतृत्व, संगठनात्मक ढांचे और विधायकों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी पार्टी की सबसे प्रभावशाली नेता बनी हुईं ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई बैठकों से जुड़े कथित दस्तावेजों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर छिड़ा सत्ता संघर्ष अब सार्वजनिक विवाद का रूप ले चुका है। इन दस्तावेजों में विधायकों की उपस्थिति, हस्ताक्षर और विभिन्न पदों के चुनाव से जुड़ी जानकारी होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर बागी खेमे के प्रमुख चेहरे और नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। इससे राज्य की राजनीति में एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है।

तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी यह विवाद केवल कुछ हस्ताक्षरों या बैठकों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी के भीतर नेतृत्व और नियंत्रण की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों ने पहले ही पार्टी को दो स्पष्ट खेमों में विभाजित कर दिया था। अब दस्तावेजों के लीक होने और उन पर उठे सवालों ने इस संघर्ष को और अधिक तीखा बना दिया है।

विवाद की शुरुआत उन दस्तावेजों से हुई, जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। दावा किया गया कि ये दस्तावेज 6 मई और 19 मई को कोलकाता के 30बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित बैठकों से संबंधित हैं। दस्तावेजों में बड़ी संख्या में विधायकों के हस्ताक्षर, उनके निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और बैठक में उपस्थिति दर्ज होने का उल्लेख दिखाई देता है। इनमें यह भी कहा गया कि संबंधित बैठकें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता तथा मुख्य सचेतक जैसे महत्वपूर्ण पदों के चयन और समर्थन से जुड़ी थीं।

वायरल दस्तावेजों के अनुसार 6 मई को आयोजित बैठक में 67 विधायकों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में यह दावा भी किया गया कि जो विधायक व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल नहीं हो सके, उन्होंने लिखित रूप से अपना समर्थन भेजा था। यदि ये दस्तावेज सही साबित होते हैं तो यह संकेत देते हैं कि पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक और विधायी रणनीति को लेकर व्यापक स्तर पर समर्थन जुटाने का प्रयास किया था। लेकिन जैसे ही ये कागजात सार्वजनिक हुए, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे।

नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी ने सबसे पहले इन दस्तावेजों की सत्यता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में दर्ज हस्ताक्षरों और उपस्थिति के दावों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार मामला पहले से जांच के दायरे में है और अब सामने आए नए दस्तावेज जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो हैंडराइटिंग विशेषज्ञों की सहायता ली जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हस्ताक्षर वास्तव में संबंधित विधायकों द्वारा किए गए हैं या नहीं।

रितब्रत बनर्जी ने केवल हस्ताक्षरों पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि दस्तावेजों की भौतिक संरचना को लेकर भी कई आपत्तियां दर्ज कीं। उनका दावा है कि दस्तावेजों के कुछ पन्नों का रंग और स्वरूप एक-दूसरे से मेल नहीं खाता। कुछ स्थानों पर हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं, जबकि कुछ पन्नों पर जानकारी अधूरी दिखाई देती है। उनके अनुसार ऐसे कई बिंदु हैं जो दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं और फर्जीवाड़े की आशंका को बल देते हैं।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जांच एजेंसियां संबंधित तिथियों पर विधायकों की मोबाइल टावर लोकेशन की जांच कर सकती हैं। यदि दस्तावेजों में जिन विधायकों की उपस्थिति दर्ज दिखाई गई है, वे वास्तव में उन दिनों कोलकाता या कालीघाट क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, तो इससे दस्तावेजों की सच्चाई पर गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि अब यह मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तकनीकी और कानूनी जांच का विषय बन गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद की जड़ें वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों में छिपी हुई हैं। चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि निर्णय प्रक्रिया कुछ सीमित नेताओं तक केंद्रित हो गई है, जबकि दूसरा पक्ष नेतृत्व के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखने की बात करता है। इसी पृष्ठभूमि में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर संघर्ष सामने आया और धीरे-धीरे यह संगठनात्मक टकराव में बदल गया।

स्थिति तब और अधिक जटिल हो गई जब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रितब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ममता बनर्जी समर्थक खेमे ने इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक और कानूनी स्तर पर चुनौती देने की बात कही। दूसरी ओर बागी विधायक लगातार यह आरोप लगाते रहे कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णय सीमित दायरे में लिए गए।

अब दस्तावेजों के लीक होने के बाद दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और गहरा होता दिखाई दे रहा है। पार्टी नेतृत्व जहां इन दस्तावेजों को समर्थन और वैध प्रक्रिया का प्रमाण मान सकता है, वहीं विरोधी गुट इन्हें कथित रूप से संदिग्ध दस्तावेज बताकर जांच की मांग कर रहा है। यही कारण है कि यह विवाद केवल पार्टी के अंदरूनी मामलों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी जांच अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी कई विधायकों के हस्ताक्षर नमूने एकत्र कर चुकी है और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। यदि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो इसके राजनीतिक और कानूनी परिणाम दूरगामी हो सकते हैं।

विवाद को और हवा तब मिली जब एक बागी विधायक ने दावा किया कि 19 मई की बैठक के दौरान दो अलग-अलग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे। उनके अनुसार एक दस्तावेज केवल उपस्थिति दर्ज करने के लिए था, जबकि दूसरा नेता प्रतिपक्ष के चयन और समर्थन से संबंधित था। इस दावे ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक पेचीदा बना दिया है, क्योंकि अब यह सवाल उठ रहा है कि हस्ताक्षर किस उद्देश्य से लिए गए थे और बाद में उनका उपयोग किस प्रकार किया गया।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, विधायकों के बयान, फॉरेंसिक विश्लेषण और विधानसभा से जुड़े संवैधानिक पहलू इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब खुले राजनीतिक संघर्ष में बदल चुकी है और 'हस्ताक्षर वॉर' के रूप में सामने आया यह विवाद पार्टी की एकता, नेतृत्व और भविष्य की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। पूरे राज्य की निगाहें अब जांच के निष्कर्षों और दोनों गुटों की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं।

पाकिस्तान की 'मध्यस्थता' पर नरवणे का तीखा प्रहार, बोले- शांति दूत नहीं, संदेश पहुंचाने वाली कूरियर सेवा बनकर रह गया है पड़ोसी देश

दुनिया के बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान की विदेश नीति और उसकी कथित कूटनीतिक भूमिका पर तीखी टिप्पणी की है। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच स्वयं को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करने की पाकिस्तान की कोशिश वास्तविकता से बहुत दूर है। उनके अनुसार पाकिस्तान किसी प्रभावशाली मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है, बल्कि वह केवल एक "कूरियर सेवा" की तरह संदेशों का आदान-प्रदान करने तक सीमित है।

जनरल नरवणे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी और संवाद स्थापित कराने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहा है। विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के दौरान पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों ने यह संकेत देने की कोशिश की थी कि वह दोनों देशों के बीच संवाद की संभावनाएं तलाशने में भूमिका निभा सकता है। हालांकि पूर्व सेना प्रमुख ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी भी देश को मध्यस्थ कहलाने के लिए दोनों पक्षों का विश्वास, प्रभाव और स्वतंत्र रणनीतिक क्षमता आवश्यक होती है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल संदेश पहुंचाने या बातचीत की इच्छा जताने से कोई देश मध्यस्थ नहीं बन जाता। वास्तविक मध्यस्थता के लिए विश्वसनीयता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वह स्वयं अनेक आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए उसे वैश्विक विवादों के समाधानकर्ता के रूप में देखना यथार्थवादी नहीं होगा।

अपने संबोधन में जनरल नरवणे ने केवल पाकिस्तान की भूमिका पर ही टिप्पणी नहीं की, बल्कि वैश्विक संघर्षों और राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक आयामों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में सुरक्षा की अवधारणा केवल सीमाओं की रक्षा या सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रह गई है। आज आर्थिक मजबूती, आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता भी राष्ट्रीय सुरक्षा के उतने ही महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुके हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा ही वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारशिला है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो वह बाहरी दबावों, वैश्विक संकटों और भू-राजनीतिक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। वहीं कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को अक्सर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जनरल नरवणे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में अर्थव्यवस्था लगभग हर निर्णय को प्रभावित करती है। चाहे वह रक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, तकनीकी विकास हो या सामाजिक स्थिरता, हर क्षेत्र की सफलता का आधार आर्थिक क्षमता ही होती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने महामारी, युद्ध, ऊर्जा संकट और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसी अनेक चुनौतियां देखी हैं। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि आर्थिक लचीलापन भी उतना ही आवश्यक है।

उन्होंने भारत की रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने हमेशा वैश्विक व्यापार व्यवस्था का हिस्सा बने रहते हुए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। भारत का उद्देश्य दुनिया से अलग-थलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत बनाना है कि किसी वैश्विक संकट का असर देश पर न्यूनतम हो। इसी सोच के तहत उत्पादन, विनिर्माण, रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमता निर्माण पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि आज की दुनिया आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट का प्रभाव सीमाओं से परे जाकर अनेक देशों तक पहुंच जाता है।

सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, साइबर हमलों की भी हुई पुष्टि

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम के बाद अंक सत्यापन और री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया से गुजर रहे लाखों विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। बोर्ड ने वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाते हुए 6 जून के स्थान पर 7 जून कर दी है। यह निर्णय उन छात्रों की लगातार आ रही शिकायतों और तकनीकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

बोर्ड के इस फैसले से उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जो अपने प्राप्त अंकों को लेकर पुनर्मूल्यांकन या सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर आवेदन नहीं कर पा रहे थे। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी केवल तकनीकी कारणों से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। सीबीएसई ने परिणाम से संबंधित सेवाओं के लिए अपना पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल 2 जून को शुरू किया था। प्रारंभिक योजना के अनुसार यह पोर्टल 1 जून से शुरू होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते इसे एक दिन बाद लॉन्च किया गया। पोर्टल शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां देखने, अंकों के सत्यापन तथा री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करना शुरू किया। हालांकि कुछ ही समय बाद कई छात्रों ने वेबसाइट की धीमी गति, लॉगिन में समस्या और आवेदन प्रक्रिया में व्यवधान जैसी शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दीं। जैसे-जैसे शिकायतों की संख्या बढ़ती गई, बोर्ड ने तकनीकी स्थिति की समीक्षा की। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पोर्टल को केवल सामान्य तकनीकी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उस पर संगठित साइबर हमले भी किए गए थे। सीबीएसई के अनुसार, पोर्टल के संचालन के शुरुआती दिनों में लगातार साइबर हमलों की कोशिशें की गईं, जिनका उद्देश्य वेबसाइट की कार्यक्षमता को प्रभावित करना था।

बोर्ड ने इस गंभीर मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब साइबर विशेषज्ञों और पुलिस की टीमों द्वारा पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल तकनीकी गड़बड़ी का मामला नहीं था, बल्कि वेबसाइट को निशाना बनाकर उसे बाधित करने की सुनियोजित कोशिशें भी की गई थीं। सीबीएसई के अधिकारियों के अनुसार, पोर्टल लॉन्च होने के तुरंत बाद कुछ अज्ञात तत्वों ने 'डिनायल ऑफ सर्विस' (डीओएस) प्रकार का साइबर हमला किया। इस हमले का उद्देश्य वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर उसे अस्थायी रूप से निष्क्रिय करना था। बोर्ड के मुताबिक, महज दो मिनट के भीतर वेबसाइट पर लगभग 15 लाख हिट्स दर्ज हुईं, जो सामान्य उपयोग से कहीं अधिक थीं। इसके अतिरिक्त एक लाख से अधिक बार अनधिकृत तरीके से फाइलों तक पहुंचने की कोशिश भी की गई।

हालांकि बोर्ड ने राहत की बात यह बताई है कि समय रहते सुरक्षा तंत्र सक्रिय कर दिए गए और सभी हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया। अब तक किसी भी छात्र के डेटा के लीक होने या किसी प्रकार की अनधिकृत पहुंच का कोई मामला सामने नहीं आया है। सीबीएसई ने आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी और परीक्षा संबंधी रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं। साइबर हमलों की गंभीरता को देखते हुए देश की कई प्रमुख तकनीकी और साइबर सुरक्षा संस्थाओं ने भी बोर्ड की सहायता की। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के विशेषज्ञों के अलावा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), सीईआरटी-इन तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों की साइबर सुरक्षा टीमें शामिल रहीं।

जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' का शक्ति प्रदर्शन सोशल मीडिया का व्यंग्य बना सियासी बहस का नया केंद्र

नई दिल्ली के जंतर-मंतर ने शनिवार को एक ऐसे आंदोलन का गवाह बना, जिसकी शुरुआत कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर व्यंग्य और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में हुई थी। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) नाम से शुरू हुआ यह अभियान अब सड़क पर उतरकर अपनी राजनीतिक और सामाजिक उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता दिखाई दिया। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे युवाओं, छात्रों और समर्थकों की मौजूदगी के बीच जंतर-मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाले अभियान अब वास्तविक जनआंदोलनों का स्वरूप भी ले सकते हैं। प्रदर्शन के केंद्र में शिक्षा, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और युवाओं की आवाज को लेकर उठ रहे सवाल रहे, जबकि मंच से सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए जवाबदेही की मांग भी की गई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया। अमेरिका से दिल्ली पहुंचने के बाद वे सीधे जंतर-मंतर पहुंचे और मंच से अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए

कहा कि देश के युवाओं के सामने रोजगार, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे गंभीर प्रश्न खड़े हैं, लेकिन इन मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। दीपके ने कहा कि शनिवार का यह प्रदर्शन केवल शुरुआत है और आने वाले समय में आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने इसे "सिर्फ ट्रेलर" बताते हुए संकेत दिया कि संगठन आगे और बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। जंतर-मंतर पर दिनभर युवाओं की भीड़ जुटी रही। विभिन्न राज्यों से आए छात्र और युवा अपने-अपने मुद्दों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। कई प्रतिभागियों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, जिनमें बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की मांगें लिखी हुई थीं। प्रदर्शन के दौरान सरकार की नीतियों के विरोध में नारे लगाए गए और युवाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाने की अपील की गई। अभिजीत दीपके ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि जो युवा रोजगार, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है या उनकी आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार की उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या संगठन का नहीं, बल्कि उन युवाओं की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। प्रदर्शन की एक विशेषता यह भी रही कि इसमें केवल छात्रों और युवाओं की भागीदारी ही नहीं रही, बल्कि कुछ प्रमुख सार्वजनिक हस्तियां भी मंच के साथ खड़ी दिखाई दीं। लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद Sonam Wangchuk ने प्रदर्शन में भाग लेकर युवाओं के मुद्दों पर संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। उनके शामिल होने से आंदोलन को अतिरिक्त चर्चा मिली। वहीं Priyanka Chaturvedi ने प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने का समर्थन करते हुए लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के अधिकार की बात कही। वरिष्ठ अधिवक्ता Prashant Bhushan ने भी इस आंदोलन को युवाओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति बताते हुए कहा कि ऐसे आंदोलनों को सकारात्मक दिशा और रचनात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी अपने आप में असामान्य मानी जा रही है। इसकी शुरुआत किसी पारंपरिक राजनीतिक संगठन की तरह नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियों और कथित अपमानजनक संदर्भों के विरोध में व्यंग्यात्मक रूप से शुरू किया गया यह अभियान धीरे-धीरे एक डिजिटल समुदाय में बदल गया। इसके समर्थकों का दावा है कि लाखों युवाओं ने ऑनलाइन माध्यमों से इससे जुड़ाव दिखाया और यह अभियान सोशल मीडिया की सीमाओं से निकलकर जनचर्चा का विषय बन गया। अब जंतर-मंतर का प्रदर्शन इस बात का संकेत माना जा रहा है कि संगठन अपने ऑनलाइन प्रभाव को वास्तविक जनसमर्थन में बदलने की कोशिश कर रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर भी इस प्रदर्शन पर बनी हुई है। उनका मानना है कि किसी भी नए आंदोलन की वास्तविक शक्ति केवल सोशल मीडिया पर मिलने वाले समर्थन से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी और उसकी निरंतरता से तय होती है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सोशल मीडिया ने जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन हर डिजिटल अभियान स्थायी जनआंदोलन में परिवर्तित नहीं हो पाता। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी अपने समर्थकों को कितने समय तक सक्रिय बनाए रख पाती है और अपने मुद्दों को किस प्रकार संगठित रूप देती है। राजनीतिक विश्लेषक Yogendra Yadav ने इसे युवाओं के भीतर उभर रही नई राजनीतिक ऊर्जा का संकेत बताया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार Rasheed Kidwai और Smita Sharma जैसे विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऑनलाइन समर्थन लगातार जमीनी उपस्थिति में बदलता रहा, तो यह देश की राजनीति में एक नए विमर्श को जन्म दे सकता है। उनके अनुसार बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, शिक्षा सुधार और संस्थागत जवाबदेही जैसे मुद्दे पहले से ही युवाओं के बीच महत्वपूर्ण हैं और यदि कोई मंच इन प्रश्नों को लगातार उठाता है, तो वह व्यापक चर्चा का केंद्र बन सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी इस प्रदर्शन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटनाक्रम सरकार और विपक्ष दोनों के लिए संकेत लेकर आया है। एक ओर सरकार के सामने युवाओं की अपेक्षाओं और असंतोष को समझने की चुनौती है, तो दूसरी ओर विपक्ष के लिए भी यह संदेश है कि नई पीढ़ी केवल पारंपरिक राजनीतिक नारों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि रोजगार, शिक्षा और पारदर्शिता जैसे ठोस मुद्दों पर जवाब चाहती है।

संपादकीय

धीमे जहर के कारोबारी

यह इंसान के पतन की पराकाष्ठा ही है कि समाज में बच्चों, वृद्धों, बीमारों व कमजोर लोगों के स्वास्थ्यवर्धन हेतु डॉक्टर दूध-घी-फल लेने को कहे, लेकिन जब उन्हें ये मिले तो उसमें भारी मिलावट पायी जाए। लोग अस्पतालों में बीमारियों से जूझते अपने परिजनों को शीघ्र ठीक करने के लिये दूध व जूस आदि देते हैं, लेकिन उनमें भी यदि घातक रसायन मिले होंगे, तो वे कैसे ठीक हो सकते हैं?
पिछले दिनों राजस्थान से अलीगढ़ लाया जा रहा सैकड़ों किलो घी बरामद हुआ। हापुड़ में करीब 22 लाख का नकली शहद पकड़ा गया। सोमनाथ में किडनी-लीवर को नुकसान पहुंचाने वाला यूरिया, डिटर्जेंट व कास्टिक सोडा मिला तीन हजार लीटर दूध बरामद होने की खबरें मीडिया में तैरती रहीं। आखिर लोभी मनुष्य के पतन की कोई सीमा भी है? चंद रुपयों के मुनाफे के लिये हम अपना दीन-ईमान बेचने के लिये कैसे तैयार हो जाते हैं? जीवन रक्षक दवा से लेकर खानपान में मिलावट की लगातार आने वाली खबरें विचलित करती हैं कि क्या खाएं और क्या न खाएं।
पहले कहा जाता था कि ऊपर वाले से डर के कह रहा हूं। लोगों में नैतिकता का भाव होता था। समाज में धारणा थी कि दूसरों के लिये कुंआ खोदने वाला खुद के लिये खाई खोद रहा होता है। लेकिन आखिर समाज में ऐसा क्या हुआ कि लोगों में दुनिया की रचना करने वाले का भय व लोककल्याण का भाव खत्म हो गया। निश्चय ही ये रामराज जैसा वक्त नहीं है। हर दौर में अच्छे-बुरे लोग होते ही हैं। नकारात्मक सोच व दूसरों को कष्ट देकर खुश होने वाले रुग्ण मानसिकता के लोग हर काल खंड में पाये जाते रहे हैं। लेकिन उनका प्रतिशत कम रहा है। आज तो हर व्यक्ति मुनाफे से रातों-रात धनी हो जाना चाहता है,अब चाहे किसी की जान भी जाए, उसकी बला से। निस्संदेह, ये घटनाएं किसी सभ्य के माथे पर कलंक जैसी ही हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि फलों को तुरत-फुरत पकाने वाले रसायनों का जमकर प्रयोग किया जा रहा है। हरी सब्जी व फलों को घातक रसायन से चमकदार बनाया जा रहा है। दरअसल, तुरंत फसल लेने के लिये ऐसे घातक रसायन प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन पर तमाम सभ्य समाजों में पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नियामक तंत्र विकसित ही नहीं हो पाया है, जो ऐसे मामलों में तुरत-फुरत जांच करे और तत्काल मिलावटखोरों को सजा दिलाए। विडंबना यह भी है कि हमारे समाज में स्वयं सेवी संगठन या जागरूक लोग इस गंभीर संकट के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। शासन-प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि हर शहर में मिलावटी सामान की जांच करने वाली लैब की सहज उपलब्धता क्यों नहीं है? जिन विभागों के अधिकारियों के पास जांच-पड़ताल का दायित्व होता है, वे चुप क्यों रहते हैं? दीपावली व अन्य त्योहारों पर जनाक्रोश के चलते कुछ छोटे हलवाइयों पर कार्रवाई होती है, मगर बड़ी मछलियां साफ बच निकलती हैं। क्या इन अधिकारियों की खामोशी में चांदी के जूते की चोट शामिल होती है? यह किसी से नहीं छिपा कि ये मलाईदार पोस्ट कितने लेन-देन के बाद मिलती हैं। राजनेताओं से लेकर अधिकारियों तक को लेन-देन के बाद ही उनकी पांचों उंगलियां घी में होती है। फिर वे भी नियुक्ति में किए गए निवेश की वसूली में जुट जाते हैं। निश्चय ही एक कारगर तंत्र को विकसित किए बिना इस घृणित कारोबार पर लगाम लगना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि जब से देश में सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग बढ़ा है, लाखों सच सामने आए हैं। अन्यथा ये सच कभी अनावृत न होते। ऐसी ही कोई कारगर तकनीक मिलावट रोकेगी। जयपुर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले दिनों पैकेज्ड फूड आइटम्स पर लिखी एक्सपायरी डेट मिटाने वाले अत्याधुनिक उपकरण बरामद किए। तो ऐसे में एक्सपायरी डेट देखकर सामान खरीदने वाला आम आदमी क्या करेगा? निश्चय ही अनैतिक रूप से मुनाफा कमाने वाले लोग सख्त सजा के हकदार हैं। देश में मिलावटखोरी रोकने के लिए तुरंत सख्त कानून बनाने की जरूरत है। अन्यथा अस्पतालों में मिलावटी खाद्य पदार्थों से लीवर-किडनी खराब करवाने वाले मरीजों की लंबी कतारें हमारे समाज की हकीकत बनी रहेगी।

आखिर आर्थिक सुनामी के राजनीतिक व आर्थिक मायने मायने क्या हैं?

> जानकार बताते हैं कि आर्थिक सुनामी कोई औपचारिक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अर्थव्यवस्था को अचानक और व्यापक झटका लगे तथा उसके प्रभाव दूरगामी हों। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं- जीडीपी वृद्धि दर में तेज गिरावट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी।

राहुल गांधी की "आर्थिक सुनामी" वाली चेतावनी को फिलहाल एक राजनीतिक चेतावनी और आर्थिक जोखिमों पर विपक्षी आक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि उनका यह कहना कि भारत निश्चित रूप से आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रहा है, अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी होगी। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इस बहस को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत में वास्तव में "आर्थिक सुनामी" आएगी या नहीं, इसका कोई निश्चित उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हाल में दी गई चेतावनी ने आर्थिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का तर्क है कि वैश्विक संकट, विशेषकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, महंगाई, ईंधन कीमतों और आर्थिक असमानता के कारण भारत एक बड़े आर्थिक झटके की ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था के पास पर्याप्त "शॉक एब्जॉर्बर" हैं—विदेशी मुद्रा भंडार, नियंत्रित महंगाई, खाद्यान्न भंडार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत कर-संग्रह जैसी व्यवस्थाएं—जो बाहरी संकटों का सामना करने में सक्षम हैं।
भारत के सामने कुछ वास्तविक चुनौतियाँ हैं: जैसे वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि की आशंका। निर्यात और निवेश पर अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर। रोजगार सृजन की चुनौती। और कृषि और एमएसएमई क्षेत्र पर दबाव। लेकिन साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है, और कई आर्थिक संकेतक अभी व्यापक संकट की पुष्टि नहीं करते।
जानकार बताते हैं कि आर्थिक सुनामी कोई औपचारिक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अर्थव्यवस्था को अचानक और व्यापक

झटका लगे तथा उसके प्रभाव दूरगामी हों। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं- जीडीपी वृद्धि दर में तेज गिरावट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। बैंकिंग या वित्तीय संकट। शेयर बाजार में भारी गिरावट। मुद्रा पर दबाव और महंगाई का बढ़ना। निवेश और उपभोग में तीव्र कमी। इतिहास में Great Depression (1930 का दशक) और Global Financial Crisis (2008) जैसी घटनाओं को आर्थिक सुनामी के उदाहरण माना जा सकता है।
किसी भी सरकार या प्रधानमंत्री के रहते हुए आर्थिक संकट की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था अनेक घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे— वैश्विक मंदी या वित्तीय संकट। तेल की कीमतों में असाधारण वृद्धि। बड़े युद्ध या भू-राजनीतिक तनाव। प्राकृतिक आपदाएं या महामारी। घरेलू नीति संबंधी गंभीर त्रुटियां। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो बड़े झटकों को सहने में मदद करती हैं— जैसे- विशाल घरेलू बाजार। अपेक्षाकृत मजबूत बैंकिंग और नियामक व्यवस्था। बढ़ता डिजिटल भुगतान तंत्र। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पर निवेश। विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर। दूसरी ओर, चुनौतियां भी मौजूद हैं—जैसे- युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन। कृषि आय में सुधार। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। और, आय असमानता और उपभोग मांग का प्रश्न।
इसलिए निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो "पीएम मोदी के रहते आर्थिक सुनामी निश्चित रूप से आएगी" या "कभी नहीं आएगी"— दोनों दावे तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं हैं। भारत की आर्थिक स्थिति कई संकेतकों पर अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है, लेकिन किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह यह वैश्विक और घरेलू जोखिमों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आर्थिक सुनामी की संभावना मुख्यतः नीतियों, वैश्विक परिस्थितियों और भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करेगी, न कि केवल किसी एक नेता की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर।
"आर्थिक सुनामी" एक रूपक (metaphor) है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यापक और तीव्र आर्थिक संकट जो समाज, बाजार, उद्योग, रोजगार और सरकार की वित्तीय स्थिति को एक साथ प्रभावित कर दे। जिस प्रकार समुद्री सुनामी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झकझोर देती है, उसी प्रकार आर्थिक सुनामी भी अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर गहरा असर डालती है। आइए जानते हैं आर्थिक सुनामी के प्रमुख संकेत के बारे में- पहला, शेयर बाजार में भारी गिरावट। दूसरा, निवेशकों की संपत्ति तेजी से घटती है। तीसरा, कंपनियों का बाजार मूल्य कम हो जाता है। चौथा, बेरोजगारी में तेज वृद्धि। पांचवां, उद्योगों और कंपनियों में छंटनी बढ़ती है। छठा, नए रोजगार सृजन की गति धीमी पड़ जाती है। सातवां, बैंकिंग और वित्तीय संकट। आठवां, ऋण वसूली की समस्या बढ़ती है। नौवां, बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर दबाव आता है। दसवां, मुद्रा और महंगाई पर असर। दसवां, राष्ट्रीय मुद्रा कमजोर हो सकती है। ग्यारहवां, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। बारहवां, व्यापार और उद्योग में मंदी। तेरहवां, उत्पादन घटता है। चौदहवां, निवेशक नए निवेश से बचते हैं। आर्थिक संकट केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि इसके राजनीतिक परिणाम भी होते हैं— पहला, सरकार की लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। दूसरा, विपक्ष को सरकार की नीतियों पर हमला करने का अवसर मिलता है। तीसरा, सामाजिक असंतोष और जनाक्रोश बढ़ सकता है। चौथा, चुनावी परिणामों पर असर पड़ सकता है। जहां तक भारत के संदर्भ में इसकी बात है तो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में "आर्थिक सुनामी" का अर्थ होगाक् विकास दर में तीव्र गिरावट, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, निवेश और उपभोग में कमी, राजकोषीय दबाव, तथा आम नागरिकों की क्रय शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव। हालांकि भारत की विशाल घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र, कृषि आधार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार जैसी ताकतें ऐसे संकटों के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती हैं।
जहां तक राहुल गांधी की आशंका के राजनीतिक मायने का सवाल है तो यह कहा जा सकता है कि आर्थिक मुद्दों को चुनावी केंद्र में लाने की कोशिश कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय और छोटे कारोबारों की समस्याओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। "आर्थिक सुनामी" जैसी अभिव्यक्ति इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है। वैसे भी मोदी सरकार के आर्थिक मॉडल पर सीधा हमला राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था बड़े कॉरपोरेट समूहों के पक्ष में झुकी हुई है। यह बयान उसी राजनीतिक विमर्श को आगे बढ़ाता है।
वहीं वैश्विक संकट को घरेलू राजनीति से जोड़ना पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों को विपक्ष सरकार की आर्थिक नीतियों की परीक्षा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। कुलमिलाकर 2029 के राजनीतिक नैरेटिव की तैयारी में कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि यदि भविष्य में आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ती हैं तो उसने पहले ही चेतावनी दी थी। वहीं भाजपा इसे "भय फैलाने की राजनीति" बताकर अपनी आर्थिक उपलब्धियों को सामने रख रही है।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक सुनामी का वास्तविक मायने केवल आर्थिक आंकड़ों का बिगड़ना नहीं, बल्कि आम आदमी की आय, रोजगार, बचत, व्यापार और जीवन-स्तर पर एक साथ पड़ने वाला व्यापक नकारात्मक प्रभाव है। यही कारण है कि जब कोई राजनीतिक नेता या अर्थशास्त्री "आर्थिक सुनामी" की चेतावनी देता है, तो उसका आशय संभावित बड़े आर्थिक और सामाजिक झटके से होता है।

प्रेरणा

रसोई से जुड़ी वह परंपरा जो मानी जाती है सुख, समृद्धि और सुरक्षा का आधार

भारतीय संस्कृति में भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं माना गया है, बल्कि इसे धर्म, सेवा, करुणा और आध्यात्मिकता से भी जोड़ा गया है। हमारे पूर्वजों ने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने के लिए अनेक ऐसी परंपराएं बनाई थीं, जिनके पीछे गहरा धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व छिपा हुआ है। इन्हीं परंपराओं में से एक है रसोई में बनी पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देने की परंपरा। आज भी देश के अनेक घरों में यह नियम श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाया जाता है।
बचपन में अक्सर दादी-नानी यह सीख देती थीं कि भोजन बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए और अंत में कुत्ते के लिए रोटी रखनी चाहिए। देखने में यह एक साधारण आदत लग सकती है, लेकिन इसके पीछे धर्म, वास्तु, पर्यावरण और मानवता से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए हैं। माना जाता है कि यह छोटी-सी परंपरा घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होती है।
हिंदू धर्म में अन्न को देवतुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भोजन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए अन्न का सम्मान करना और उसे जरूरतमंद जीवों के साथ साझा करना पुण्य का कार्य माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपने भोजन का एक हिस्सा अन्य जीवों को समर्पित करता है, तो वह केवल दान नहीं करता बल्कि प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाता है। इसी भावना के कारण पहली और आखिरी रोटी की परंपरा विकसित हुई।
गाय को सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। उसे गौ माता कहा जाता है और मान्यता है कि उसके शरीर में अनेक देवी-देवताओं का निवास होता है। धार्मिक ग्रंथों में गाय की सेवा को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को भोजन कराता है, उसके जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। पहली रोटी गाय को देने का अर्थ है कि दिन की शुरुआत सेवा और श्रद्धा के साथ की जाए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां गौ सेवा होती है, वहां धन, धान्य और खुशहाली का वास होता है। कई लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की उन्नति के लिए भी नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाते हैं। विशेष रूप से गुरुवार, सोमवार और अमावस्या के दिन गाय को भोजन कराने का महत्व अधिक बताया गया है।
वास्तु शास्त्र में भी गाय को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। मान्यता है कि गाय को भोजन देने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और वातावरण में शांति बनी रहती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। कई वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि यदि घर में लगातार आर्थिक या मानसिक समस्याएं बनी रहती हैं तो गौ सेवा करने से लाभ मिल सकता है।
जहां पहली रोटी गाय के लिए निर्धारित की जाती है, वहीं आखिरी रोटी कुत्ते को देने की परंपरा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। हिंदू धर्म में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना जाता है। काल भैरव भगवान शिव का ही एक उग्र और शक्तिशाली स्वरूप हैं। इसलिए कुत्ते को भोजन कराना भैरव देव की सेवा के समान माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। कई लोग इसे शनि, राहु और केतु से संबंधित दोषों को शांत करने का उपाय भी मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु या केतु की स्थिति प्रतिकूल हो तो काले या भूरे रंग के कुत्ते को भोजन कराने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार कुत्ते को भोजन देने से घर के आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। इसे बुरी नजर, भय और अनचाही बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करने वाला उपाय माना जाता है। कई परिवार आज भी प्रतिदिन कुत्तों को रोटी या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाकर इस परंपरा का पालन करते हैं। धार्मिक और वास्तु महत्व के अलावा इस परंपरा का सामाजिक और मानवीय पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास अनेक पशु-पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें नियमित भोजन नहीं मिल पाता। यदि प्रत्येक परिवार अपने भोजन का थोड़ा-सा हिस्सा इन जीवों के लिए अलग रखे, तो अनेक पशुओं की भूख मिट सकती है। यह परंपरा हमें दया, करुणा और सह-अस्तित्व का संदेश देती है।
भारतीय संस्कृति हमेशा से "सर्वे भवन्तु सुखिनः" की भावना पर आधारित रही है। इसका अर्थ केवल मनुष्यों का कल्याण नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति संवेदनशील होना भी है। गाय और कुत्ते को रोटी देने की परंपरा इसी सोच का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति के प्रत्येक प्राणी का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें उनके प्रति भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पशुओं को भोजन देने से मनुष्य के भीतर सकारात्मक भावनाओं का विकास होता है। कई शोधों में यह पाया गया है कि पशुओं की सेवा करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सहायता करता है, तो उसके भीतर संतोष और प्रसन्नता की भावना उत्पन्न होती है।
आज के आधुनिक जीवन में भले ही कई परंपराएं धीरे-धीरे कम होती जा रही हों, लेकिन पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देने की परंपरा आज भी लाखों परिवारों में जीवित है। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि सेवा, करुणा, पर्यावरण संरक्षण और सकारात्मक सोच का सुंदर संगम है। यदि इस परंपरा को सही भावना के साथ निभाया जाए, तो यह न केवल आध्यात्मिक संतोष प्रदान करती है बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी स्मरण कराती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में इन दो साधारण रोटियों को भी विशेष महत्व दिया गया है और इन्हें घर की सुख-समृद्धि तथा मंगल का प्रतीक माना जाता है।

विदेश मंत्री रूबियों देश के नेताओं को दिखा गए आईना

भारत दौर पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दुनिया के हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं। हम इन्हें गंभीरता से लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी बेवकूफ लोग मौजूद हैं। 'क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग' (क्वाड) की बैठक में शिरकत करने राजधानी दिल्ली में आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अमरीका में भारतीयों पर नस्लीय हमलों को लेकर यह जवाब दिया। रुबियो ने कहा कि मैं नस्लभेदी कमेंट्स को बहुत गंभीरता से लूंगा। मुझे यकीन है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन और दूसरी जगहों पर कमेंट्स किए हैं, क्योंकि दुनिया के हर देश में बेवकूफ लोग मौजूद होते हैं। मुझे यकीन है कि यहां भी बेवकूफ लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बेवकूफ लोग हैं जो हर समय बेवकूफी भरे कमेंट्स करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही वेलकमिंग देश है। दुनिया भर से हमारे देश में आने वाले लोगों से फायदा हुआ है। अमरीकी विदेश मंत्री को शायद अंदाजा होगा कि नस्लवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद भारत के अभिन्न अंग हैं। इन मुद्दों पर राजनीतिक करके देश को कमजोर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने में भारत के राजनीतिक दल ही सबसे आगे हैं। इसमें चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, कोई भी अपने राजनीतिक स्वार्थों को भुनाने में पीछे नहीं रहता। सत्ता में जो भी राजनीतिक दल होता है, वह यंत्रणा और क्रूरता को कानूनी आड़ में जायज ठहराने का प्रयास करता है। इसका देश में सबसे बड़ा उदाहरण है पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें। अमरीका में एक अश्वेत युवक की पुलिसकर्मियों ने हत्या कर दी थी। इससे पूरे अमरीका में बवाल मच गया था। 25 मई 2020 को मिनियापोलिस शहर में 'डेरेक शॉविन' नामक एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के निहत्थे अश्वेत व्यक्ति की गर्दन पर लगभग 9 मिनट तक अपना घुटना दबाए रखा था, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद "ब्लैक लाइव्स मैटर" आंदोलन के तहत अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुए। आरोपी पुलिस अधिकारी को हत्या का दोषी ठहराया गया और 2021 में उसे 22.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके विपरीत भारत में पुलिस हिरासत में मौतें साधारण घटनाओं में शुमार है। सरकारी तंत्र को ऐसी मौतों से खास फर्क नहीं पड़ता। सरकार ऐसी मौतों को कभी गंभीरता से नहीं लेती। कारण साफ है ऐसी मौतों में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर सत्तातंत्र जिम्मेदार होता है। यही वजह है कि हिरासत में मौतों जैसे बेहद अमानवीय और संवदेनशील मुद्दे पर भी सरकारें खामोश रहती हैं। विपक्ष जरूर कुछ शोर मचाता है, किन्तु विपक्ष जब सत्ता में रहा होता है, तब भी ऐसी मौतें होती रही हैं, इसलिए सत्ता पक्ष द्वारा गढ़े मुर्दे उखाड़े जाने के भय विपक्ष प्रायः चुप्पी ही साधे रहता है। अदालतों ने भारत में पुलिस हिरासत में मौतें रोकने के प्रयास किए हैं, किन्तु सफल नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में होने वाली हिंसा को व्यवस्था पर धब्बा बताया था। ऐसी मौतों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का सख़्त सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार हमें हल्के में ले रही है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, "अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं। "शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ यह सख्त टिप्पणी की थी। हिरासत में मौतों पर अपवादस्वरूप ही दोषी पुलिसकर्मियों को अदालतों से सजा मिल पाती है। अप्रैल 2026 में, एक ऐतिहासिक और दुर्लभतम फैसले में मदुरै की एक अदालत ने वर्ष 2020 में पुलिस हिरासत में एक पिता (पी. जयराज) और पुत्र (जे. बेनिक्स) की बेरहमी से हत्या करने के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई। जबकि अधिकतर मामलों में सबूतों के अभाव या गवाहों के मुकरने के कारण पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराना मुश्किल होता है, जिसके चलते कई मामलों में पुलिसकर्मियों को केवल विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ता है या वे बरी हो जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार वर्ष 2024 में 2,739 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। हिरासत में यातना सत्ता तंत्र की शक्ति और संवैधानिक मूल्यों का घोर दुरुपयोग है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हिरासत में रखे गए लोग कमजोर और असुरक्षित स्थिति में होते हैं और वहाँ शक्ति का संतुलन भी उनके खिलाफ होता है। जवाबदेही तय करने की स्वतंत्र जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि हिरासत में हुई मौतों की जांच अक्सर उसी पुलिस विभाग द्वारा की जाती है, जिनके संरक्षण में ऐसी घटना घटित होती है। यातना के उपयोग को पुलिस बल के भीतर हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने से जोड़ा गया है। भारत में यातना (टॉर्चर) को रोकने या उससे निपटने के लिए अब तक कोई विशेष, स्वतंत्र कानून नहीं बन पाया है। यद्यपि भारत ने 1997 में 'संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी सम्मेलन' पर हस्ताक्षर किए थेलेकिन वर्तमान में यातना से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता और भारतीय संविधान के प्रावधानों का ही उपयोग किया जाता है। यातना निवारण विधेयक 2010 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन की पुष्टि करना और यातना को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध बनाना था। हालाँकि, प्रवर समिति को भेजे जाने और संशोधनों की सिफारिशों के बाद, यह विधेयक लैप्स हो गया और कानून का रूप नहीं ले सका। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि भारत में हर साल सैकड़ों लोग हिरासत में मारे जाते हैं। उनका कहना है कि संदिग्धों से जबरन कबूलनामा निकलवाने के लिए यातना और दुर्व्यवहार करना पुलिसिंग का हिस्सा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के कई विशेषज्ञों ने भारत से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़े सुधार करने का आह्वान किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब हिरासत में मौतों को लेकर देश की सरकारों को खास फर्क नहीं पड़ता, तब अमरीकी विदेश मंत्री को अमरीका में मौजूद मामूली से नस्लवाद को लेकर शर्मिंदा होना देश के नेताओं को आईना दिखाने जैसा है।

अभियान

मां वाग्देवी की वापसी का आह्वान: जब सात सौ वर्षों की मौन पुकार सुनने लगा इतिहास

भारत की पवित्र भूमि केवल राजाओं और साम्राज्यों की गाथाओं से नहीं बनी है, बल्कि यह उन मंदिरों, तीर्थों और ज्ञानपीठों की भी धरती है, जहां सदियों तक ऋषियों की तपस्या, विद्वानों की साधना और भक्तों की आस्था ने संस्कृति का दीपक प्रज्वलित रखा। मध्यप्रदेश की प्राचीन धरा पर स्थित धार की भोजशाला भी ऐसा ही एक दिव्य स्थल है, जिसकी पहचान केवल पत्थरों और स्थापत्य से नहीं, बल्कि मां सरस्वती की अनंत कृपा, राजा भोज के अद्वितीय ज्ञान और सनातन संस्कृति की अमर चेतना से जुड़ी हुई है। आज जब भोजशाला एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बनी है, तब यह केवल किसी भवन या परिसर की बात नहीं रह जाती, बल्कि यह उस आत्मा की कथा बन जाती है जो सात सौ वर्षों तक मौन रहकर भी जीवित रही और अपने पुनर्जागरण की प्रतीक्षा करती रही।
कहा जाता है कि जब भी किसी भूमि पर ज्ञान का सूर्य उदित होता है, वहां देवत्व स्वयं निवास करने लगता है। धार नगरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। परमार वंश के महान सम्राट राजा भोज ने जब इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया, तब उन्होंने केवल राजसत्ता का विस्तार नहीं किया, बल्कि ज्ञान, कला, साहित्य और धर्म का ऐसा केंद्र स्थापित किया जिसकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। भोजशाला उसी स्वर्णिम युग की अनुपम देन थी। यह वह स्थान था जहां वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं, जहां संस्कृत की विद्वत सभाएं लगती थीं, जहां शास्त्रार्थ होते थे और जहां मां वाग्देवी की आराधना को जीवन का सर्वोच्च साधन माना जाता था।
भोजशाला केवल एक मंदिर नहीं थी, वह ज्ञान की तपोभूमि थी। यहां आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं को मां सरस्वती की शरण में समर्पित मानता था। यहां के प्रांगण में बैठकर विद्वान धर्म, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष और साहित्य पर चिंतन करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर प्राप्त होने वाला ज्ञान केवल सांसारिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण के लिए भी था। इसलिए भोजशाला को केवल शिक्षण केंद्र कहना उसके वास्तविक महत्व को छोटा कर देना होगा। यह तो ज्ञान और भक्ति का ऐसा संगम था, जहां बुद्धि और श्रद्धा दोनों एक साथ विकसित होते थे।
समय का चक्र घूमता रहा और भारत ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे। विदेशी आक्रमणों की आंधियां आईं, अनेक मंदिर खंडित हुए, कई विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए और सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने के प्रयास हुए। भोजशाला भी इस पीड़ा से अछूती नहीं रही। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सत्य को पूरी तरह मिटने नहीं देता। भले ही भवनों को क्षति पहुंच जाए, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रहती है। भोजशाला की आत्मा भी जीवित रही। इसके स्तंभों में इतिहास सांस लेता रहा, इसकी दीवारों में संस्कृति की स्मृतियां सुरक्षित रहीं और इसकी भूमि पर मां वाग्देवी की कृपा बनी रही।
जब कोई श्रद्धालु भोजशाला के परिसर में प्रवेश करता है, तो उसे केवल पुरातात्विक अवशेष नहीं दिखाई देते। उसे ऐसा अनुभव होता है मानो हर पत्थर किसी भूली हुई कथा को सुनाना चाहता हो। यहां अंकित संस्कृत शिलालेख, प्राचीन प्रतीक, वैदिक चिह्न और कलात्मक नक्काशियां उस युग की साक्षी हैं, जब भारत ज्ञान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता था। ऐसा लगता है मानो इन दीवारों में आज भी वेदपाठ की ध्वनि गूंज रही हो और मां सरस्वती के चरणों में समर्पित स्तुतियां वातावरण में तैर रही हों।
भोजशाला का उल्लेख आते ही मां वाग्देवी की दिव्य प्रतिमा का स्मरण अनायास हो जाता है। यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का साकार स्वरूप मानी जाती थी। विद्वानों का मानना था कि उसकी दिव्यता इतनी अद्भुत थी कि उसे देखकर मन स्वतः भक्ति और श्रद्धा से भर उठता था। मां के करकमलों में ज्ञान का संदेश था, उनके मुखमंडल पर करुणा का प्रकाश था और उनकी मुद्रा में संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करने वाली चेतना का आभास मिलता था। यही कारण है कि आज भी करोड़ों श्रद्धालु उस प्रतिमा की वापसी की कामना करते हैं।
भोजशाला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भक्ति और विद्या एक-दूसरे से अलग नहीं थीं। सनातन परंपरा में ज्ञान को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग माना गया है। मां सरस्वती केवल शिक्षा की देवी नहीं हैं, वे विवेक, सत्य और आत्मज्ञान की अधिष्ठात्री भी हैं। इसलिए भोजशाला का महत्व केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यहां की मिट्टी में उन हजारों विद्यार्थियों की तपस्या समाई हुई है जिन्होंने ज्ञान को साधना माना और मां वाग्देवी को अपना पथप्रदर्शक स्वीकार किया।
सदियों के संघर्ष के बाद जब भोजशाला को लेकर नए तथ्य सामने आए और पुरातात्विक अध्ययन ने इसके प्राचीन स्वरूप पर प्रकाश डाला, तब अनेक लोगों ने इसे केवल एक कानूनी प्रक्रिया के रूप में देखा। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह उससे कहीं अधिक था। उनके लिए यह विश्वास की विजय थी। यह उस धैर्य की जीत थी जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बना रहा। यह उन प्रार्थनाओं का उत्तर था जो वर्षों से मां सरस्वती के चरणों में अर्पित की जाती रही थीं। आज भोजशाला का नाम लेते ही अनेक लोगों की आंखों में एक विशेष चमक दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय फिर से जीवित हो रहा है। यह केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना भी है। जिस भूमि पर कभी ज्ञान के दीप जलते थे, वहां फिर से अध्ययन, संस्कृति और आध्यात्मिकता का वातावरण विकसित हो सकता है। यही कारण है कि अनेक लोग भोजशाला को केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक मानते हैं।
मां वाग्देवी की प्रतिमा की वापसी की प्रतीक्षा भी इसी भावना का हिस्सा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जिस दिन मां पुनः अपने धाम में विराजमान होंगी, वह दिन केवल धार के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए उत्सव का दिन होगा। वह क्षण सनातन संस्कृति की एक ऐतिहासिक स्मृति को पुनर्जीवित करने वाला होगा। तब शायद भोजशाला के प्रांगण में फिर से वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दे, फिर से वसंत पंचमी का उत्सव उसी भव्यता से मनाया जाए और फिर से विद्यार्थी मां सरस्वती के चरणों में ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लें।
भोजशाला की कथा हमें यह भी सिखाती है कि आस्था कभी पराजित नहीं होती। समय उसे चुनौती दे सकता है, परिस्थितियां उसे रोक सकती हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा को समाप्त नहीं कर सकतीं। सात सौ वर्षों का यह लंबा कालखंड इसी सत्य का प्रमाण है। जिन्होंने इस स्थान की महिमा को अपने हृदय में जीवित रखा, उन्होंने केवल एक भवन की रक्षा नहीं की, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखा।
आज जब सूर्य की किरणें भोजशाला के प्राचीन स्तंभों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं मुस्कुरा रहा हो। मानो राजा भोज की तपस्या, मां सरस्वती की कृपा और असंख्य भक्तों की प्रार्थनाएं एक साथ मिलकर नए युग का स्वागत कर रही हों। यह केवल एक धरोहर नहीं, बल्कि एक संदेश है कि ज्ञान, संस्कृति और श्रद्धा की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उन्हें उतना ही कठिन होता है मिटा पाना।
भोजशाला आज भी खड़ी है, समय की हर परीक्षा को पार करके। उसके स्तंभ आज भी सनातन गौरव की कथा कहते हैं। उसकी दीवारें आज भी ज्ञान की महिमा का गुणगान करती हैं। उसकी पवित्र भूमि आज भी मां वाग्देवी के चरणचिह्नों को स्मरण करती है। और करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय आज भी उसी विश्वास से भरे हुए हैं कि ज्ञान की देवी का यह पावन धाम एक बार फिर अपने पूर्ण वैभव, दिव्यता और आध्यात्मिक प्रकाश के साथ समस्त भारतवर्ष को आलोकित करेगा।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सॉइल हेल्थ कार्ड : भूमि का एक्स-रे

गुजरात में पिछले दो दशकों में 2.23 करोड़ से अधिक किसानों ने निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए

▸▸ चालू वर्ष में गुजरात में 2.18 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य

▸▸ सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रभाव : भावनगर के किसान श्री हिरेनभाई का उर्वरकों का उपयोग 370 किलोग्राम घटा; फिर भी उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा

▸▸ सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों का पालन करने से सुरेंद्रनगर के श्री अरुणभाई की जमीन अधिक उपजाऊ बनी

▸▸ गुजरात में सॉइल टेस्टिंग के लिए 22 प्रयोगशालाएं कार्यरत गुजरात में सॉइल टेस्टिंग के लिए 22 प्रयोगशालाएं कार्यरत : 12 तत्वों का होता है परीक्षण

गांधीनगर : भावनगर के गारियाधार गांव के किसान श्री हिरेनभाई नाकराणी के पास 12 बीघा जमीन है। वे वर्षों से कपास की खेती कर रहे हैं। कपास की फसल में वे हर वर्ष 400 किलोग्राम यूरिया और 290 किलोग्राम डीएपी का उपयोग करते थे। इससे उनकी खेती की लागत अधिक रहती थी और उत्पादन केवल 200 मन तक ही सीमित रहता था।

श्री हिरेनभाई ने ग्रामसेवक की सलाह पर भावनगर की सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशाला में अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई। मिट्टी परीक्षण के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड में दी गई सिफारिशों के अनुसार उन्होंने अपने खेत में यूरिया का उपयोग 180 किलोग्राम तथा डीएपी का उपयोग 140 किलोग्राम कर दिया। इस प्रकार 220 किलोग्राम यूरिया और 150 किलोग्राम डीएपी की बचत हुई, जिससे खेती की लागत लगभग आधी हो गई। साथ ही वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से उत्पादन भी 200 मन से बढ़कर 281 मन हो गया।

श्री हिरेनभाई कहते हैं, "पहले हम अंधेरे में तीर चलाते थे। अधिक उत्पादन पाने के लिए अंधाधुंध उर्वरकों की बोरियां खेत में डालते रहते थे और जमीन को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन जब हमारे हाथ में सॉइल हेल्थ कार्ड आया, तब पता चला कि यह तो हमारी जमीन की एक्स-रे रिपोर्ट है। अब हम सिफारिश के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही उर्वरक उपयोग करते हैं। इससे लागत आधी हो गई है और फसल भरपूर होने लगी है।"

भावनगर के हिरेनभाई की तरह राज्य के लाखों किसानों ने पिछले दो दशकों में 2.23 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड निःशुल्क बनवाए हैं। चालू वर्ष में भी राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से जमीन के 2.18 लाख नमूनों की जांच कर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सॉइल हेल्थ कार्ड से खेती की लागत कम होने और आय बढ़ने के अलावा भूमि अधिक स्वस्थ और उपजाऊ भी बनती है। सुरेंद्रनगर जिले के लिखतर तहसील के किसान श्री अरुणभाई मेणिया ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, "सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण मेरी जमीन की जांच हुई और मैंने जैविक खाद का उपयोग शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप मेरे खेत की कठोर हो चुकी जमीन नरम हो गई और मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता में वृद्धि हुई।" इस प्रकार श्री हिरेनभाई और श्री अरुणभाई जैसे अनेक किसानों की खेती में सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से बड़ा परिवर्तन आया है।

सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है और किसान को इससे क्या लाभ होता है?

गांधीनगर सॉइल टेस्टिंग लैब की सहायक कृषि निदेशक श्रीमती पारुल परमार बताती हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड में मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जैसे 6 प्रमुख तत्वों तथा कॉपर, आयरन, जिंक और मैंगनीज जैसे 6 सूक्ष्म तत्वों सहित कुल 12 मानकों का पृथ्थकरण किया जाता है। इस पृथ्थकरण के आधार पर किसानों को उर्वरकों के उपयोग संबंधी सिफारिशें दी जाती हैं। इन सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने से अनावश्यक खर्च रुकता है और जमीन भी स्वस्थ बनी रहती है। गुजरात में वर्तमान में मिट्टी परीक्षण के लिए 21 प्रयोगशालाएं और एक सूक्ष्म तत्व प्रयोगशाला कार्यरत हैं।

सॉइल टेस्टिंग के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लें?

सहायक कृषि निदेशक श्री सापरिया बताते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड से सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित पद्धति से मिट्टी का नमूना लेना अत्यंत आवश्यक है। खेत की मेड़, रास्ते, पानी भरने वाले क्षेत्र अथवा पेड़ों की छाया से दूर रहकर एक हेक्टेयर क्षेत्र में 10 से 20 अलग-अलग स्थानों से जिग-जैग पद्धति द्वारा 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर नमूना लेना चाहिए। एकत्रित मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर चार भागों में बांटना चाहिए और उनमें से दो भाग अलग कर देने चाहिए। इसके बाद शेष मिट्टी को पुनः मिलाकर उसमें से 500 ग्राम मिट्टी का नमूना परीक्षण के लिए भेजना चाहिए। इस प्रक्रिया से परीक्षण का परिणाम अधिक सटीक प्राप्त होता है।

सॉइल हेल्थ कार्ड की अवधारणा और विस्तार

वर्ष 2003-04 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देखा कि राज्य में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण धरती माता अपनी उर्वरता खो रही है। उन्होंने विचार किया कि यदि मनुष्य के शरीर की जांच के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किए जा सकते हैं, तो धरती माता के स्वास्थ्य की जांच क्यों नहीं की जा सकती? इसी विचार से 'सॉइल हेल्थ कार्ड योजना' का जन्म हुआ।

गुजरात ने देश में सबसे पहले यह प्रयोग किया और इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। आज यह उनके कार्यकाल की ऐसी मूक क्रांति मानी जाती है, जिसने देश के अनेक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

देश के किसी छोटे से गांव में बैठा किसान जब विज्ञान और खेती के इस समन्वय की बात करता है, तब यह समझ में आता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' का जो नारा वर्षों पहले गुजरात की धरती से गूंजा था, वह आज देश के करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाला महामंत्र बन चुका है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल के वर्ष इस बात का प्रमाण हैं कि वास्तविक क्रांति वही होती है, जो जमीन से जुड़ी होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड आज भारतीय कृषि क्षेत्र का एक सुरक्षा कवच बन चुका है। जब देश की भूमि स्वस्थ होती है, तभी किसान समृद्ध बनता है और यही समृद्धि 'आत्मनिर्भर भारत' की वास्तविक नींव है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर साबरमती लोकोशेड एवं रेलवे हॉस्पिटल में व्यापक वृक्षारोपण

"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत विभिन्न रेल परिसरों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं हरित भविष्य के संकल्प के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

साबरमती स्थित लोकोमोटिव शेड में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (Sr. DME) श्री एस. पी. गुप्ता के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुपरवाइजरों, तकनीकी कर्मचारियों एवं अन्य रेलकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संतुलन के लिए ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के स्वस्थ जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। सभी कर्मचारियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया।

इसी क्रम में मंडल रेलवे हॉस्पिटल, साबरमती में अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज देव के नेतृत्व में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। डॉ. देव ने कहा कि स्वच्छ वायु और हरित वातावरण अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला हैं तथा अस्पताल परिसर को और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए ऐसे प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल के विभिन्न स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों तथा ट्रैक किनारे भी नीम, पीपल, बरगद, गुलमोहर एवं जामुन जैसे स्वदेशी पौधों का रोपण किया गया। अहमदाबाद मंडल भारतीय रेलवे के "नेट जीरो कार्बन एमिशन" लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत एवं हरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी असारवा और आगरा केंट के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए असारवा और आगरा केंट के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 01909/01910 असारवा-आगरा केंट स्पेशल (कुल 16 ट्रिप)

ट्रेन संख्या 01909 असारवा-आगरा केंट स्पेशल 09 जून से 28 जुलाई 2026 तक प्रति मंगलवार असारवा से प्रतिदिन 15.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07.45 बजे आगरा केंट पहुंचेगी। इस तरह ट्रेन संख्या 01910 आगरा केंट-असारवा स्पेशल 08 जून से 27 जुलाई 2026 तक प्रति सोमवार आगरा केंट से प्रतिदिन 18.10 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11.10 बजे असारवा पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, सेमारी, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, मांडल गढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, रूपबास और फतेहपुर सीकरी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन सं. 01909 की बुकिंग 07 जून 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति कार्य के निरीक्षण के लिए स्थलों का दौरा किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को राज्य में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति कार्य के निरीक्षण के लिए स्थलों का दौरा किया। महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में अहमदाबाद से गांधीनगर तक कुल 37.60 किलोमीटर लंबाई में रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तीनों चरणों (फेज) के कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने परियोजनाओं के कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

मुख्यमंत्री ने गांधीनगर के निकट निर्माणाधीन गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जीटीयू) के नए कैम्पस के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। वहीं दूसरी तरफ कराई स्थित नर्मदा नहर से पीडीईयू, पीडीईयू से शाहपुर ब्रिज तथा शाहपुर ब्रिज से चिलोडा ब्रिज तक कुल 17.20 किलोमीटर लंबाई के कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा प्रगति पर हैं।

इस परियोजना के पूर्ण होने से गांधीनगर महानगर एवं गिफ्ट सिटी क्षेत्र के नागरिकों को एक आकर्षक पर्यटन स्थल उपलब्ध होगा। साथ ही; रोड कनेक्टिविटी से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी और अधिक सुदृढ़ होंगी।

परियोजना के तीनों फेज का कार्य वर्ष 2027 के अंत तक पूर्ण होने तथा लेकावाडा में 100 एकड़ भूमि पर निर्मित हो रहे जीटीयू भवन का कार्य आगामी अक्टूबर तक पूरा होने का अनुमान है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जल संसाधन एवं जल आपूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़ तथा वरिष्ठ सचिवों ने आवश्यक पूरक जानकारी प्रदान की।

12 वर्षों का लंबा संघर्ष और पिता की आंखों में खुशी के आंसू : आगरा के मासूम बच्चे के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल बना 'देवदूत'

जहां सारी आशाएं टूट गई थीं, वहां गुजरात सरकार ने दिया सहारा उत्तर प्रदेश के गरीब किसान के बेटे की जटिल सर्जरी सफल

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया के नेतृत्व में गुजरात सरकार की प्रजानोन्मुखी स्वास्थ्य नीति और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक बार फिर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में देखने को मिला है। सिविल अस्पताल के बाल रोग (पीडियाट्रिक सर्जरी) विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जरी कर उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार के 12 वर्षीय बालक को नया जीवन दिया है। मात्र 25 दिन की नवजात अवस्था की उम्र में कुत्ते के हमले का शिकार बने इस बच्चे के जननांग का 12 वर्ष बाद सफल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी द्वारा फिर से सामान्य किया गया।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने भी इस अनूठी उपलब्धि के लिए सिविल की पूरी मेडिकल टीम को बधाई देते हुए कहा कि गुजरात सरकार के आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण ही आज देश और दुनिया भर के मरीजों को ऐसी जटिल चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी सुरेश यादव का पुत्र जब मात्र 25 दिन का था, तब एक कुत्ते ने उस पर हमला कर उसके बाह्य जननांग को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, उसकी परेशानियां भी असहनीय होती गईं। बच्चे को पेशाब करने में अत्यंत कठिनाई होती थी और उसके जननांग का विकास पूरी तरह रुक गया था। कई स्थानों पर उपचार कराने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। अंततः यह परिवार उम्मीद लेकर अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचा।

बच्चे को 1 मई, 2026 को भर्ती किए जाने के बाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं बाल रोग सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. राकेश जोशी ने जांच की। जांच में पता चला कि बच्चे के दोनों वृषण (टेस्टिस) अनुपस्थित थे, लिंग अंदर की ओर दब गया था तथा मूत्रमार्ग का छिद्र अत्यंत संकरा हो गया था।

सभी चुनौतियों के बावजूद 6 मई, 2026 को डॉ. राकेश जोशी और प्रोफेसर डॉ. जयश्री रामजी के नेतृत्व में तथा एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. मृणालिनी और उनकी टीम की देखरेख में जटिल जननांग पुनर्निर्माण सर्जरी (जेनिटल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी) के साथ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी सफलतापूर्वक की गई।

14 दिनों की सघन देखरेख के बाद जब कैथेटर (पेशाब की नली) हटाई गई, तब बच्चे ने बिना किसी पीड़ा के सामान्य रूप से पेशाब किया। वर्षों बाद अपने बेटे को सामान्य स्थिति में देखकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने गुजरात सरकार तथा सिविल अस्पताल के चिकित्सकों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, भावनगर में विश्व पर्यावरण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं रेलवे बोर्ड के पर्यावरण संरक्षण संबंधी निर्देशों के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 05 जून 2026 को मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, भावनगर (DRH/BVP) के उद्यान परिसर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों एवं कर्मचारियों में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ सभी उपस्थित कर्मचारियों एवं चिकित्सकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ ग्रहण कर किया गया। इसके पश्चात प्रतिभागियों को चार टीमों – टीम A, टीम B, टीम C एवं टीम D – में विभाजित कर पर्यावरण विषयक विभिन्न रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत "Carry Water Carefully Challenge", "Waste Segregation Competition", "Green Treasure Hunt" तथा "Environment Puzzle Challenge" जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जल संरक्षण, कचरा पृथक्करण, पर्यावरणीय जागरूकता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा दिया गया। सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह, खेल भावना एवं टीमवर्क का परिचय देते हुए प्रतियोगिताओं में सक्रिय सहभागिता निभाई तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों को व्यवहारिक रूप से आत्मसात किया।

सभी प्रतियोगिताओं के अंकों के समेकित मूल्यांकन के उपरांत डॉ. मोनिका के नेतृत्व वाली टीम D ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा "ग्रीन चैंपियन–2026" का खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को कार्यक्रम के समापन अवसर पर सम्मानित किया गया।

यह आयोजन न केवल मनोरंजन एवं सहभागिता का माध्यम बना, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व एवं जन-जागरूकता को सशक्त बनाने में भी सफल रहा। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन एवं समूह छायाचित्र के साथ हुआ।

पश्चिम रेल्वे

विभिन्न शेड कार्य

डिवीजनल रेलवे मेनेजर (WA), वेस्टर्न रेलवे, 6वीं मंज़िल, इंजी. डिपार्टमेंट, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400 008 ई-टेंडर नोटिस नंबर BCT/26-27/57 दिनांक 02/06/2026 आमंत्रित करता है। काम और जगह: चलथान- चलथान गुड्स शेड में (560m x 10m) के RL प्लेटफॉर्म पर 20 ft ऊंचे कवर शेड की सुविधा का डेवलपमेंट, जिसमें लाइटिंग की सुविधा भी होगी (इलेक्ट्रिकल हिस्से सहित कंपोजिट टेंडर)। काम की लगभग कीमत: ₹ 8,33,07,272.43/- EMD: ₹ 16,66,200.00/- जमा करने की तारीख और समय: दि. 26.06.2026 को 15.00 बजे तक। खुलने की तारीख और समय: दि. 26.06.2026 को 15.30 बजे तक। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं।

0192

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

1. हियरींग/ग्रुप 1/26-27 तारीख 27.05.2026 EOI नंबर CA 11/NFR/कंसल्टेंट 2. काम का नाम और जगह: वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर कमर्शियल जगह/एसेट और खाली रेलवे ज़मीन के बेहतर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कंसल्टेंट को काम पर रखने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट (EOI) ग्रुप-1: इंदौर, देवास और डॉ. अंबेडकर नगर। 3. काम का विवरण: यह EOI वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर कमर्शियल जगह/एसेट और खाली रेलवे ज़मीन के बेहतर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कंसल्टेंट को काम पर रखने के लिए जारी किया गया है। ग्रुप-1: इंदौर, देवास और डॉ. अंबेडकर नगर। 4. काम की अवधि: 6 महीने। 5. बोली जमा करने और EOI खोलने की तारीख और समय: EOI बॉक्स दि. 11.06.2026 को सुबह 10:00 बजे रखा जाएगा EOI बॉक्स बंद होने का समय: दि. 11.06.2026 को सुबह 11:00 बजे. EOI बॉक्स खुलने का समय: दि. 11.06.2026 को सुबह 11:30 बजे, डिविजनल रेलवे मेनेजर (कमर्शियल) का ऑफिस, वेस्टर्न रेलवे, दो बत्ती, रतलाम (M.P.)। 6. वेबसाइट की जानकारी और नोटिस बोर्ड की जगह: EOI डॉक्यूमेंट वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट www.wr.indianrailways.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही DRM ऑफिस और रतलाम स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

V/087

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे आसरवा ⇌ आगरा कैंट के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाएगी

ट्रेन संख्या	प्रारंभिक स्टेशन एवं गंतव्य स्टेशन	सेवा की तिथियां	प्रस्थान	आगमन
01919	आसरवा – आगरा कैंट	09/06/2026 से 28/07/2026	15:00 बजे (मंगलवार)	07:45 बजे (अगले दिन)
01920	आगरा कैंट – आसरवा	08/06/2026 से 27/07/2026	18:10 बजे (सोमवार)	11:10 बजे (अगले दिन)

ठहराव: हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, सेमारी, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, मांडलगढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, रूपबास तथा फतेहपुर सीकरी स्टेशन दोनों दिशाओं में।

संरचना: एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच।

ठहराव के समय एवं ट्रेन की संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ।

ट्रेन संख्या 01919 की बुकिंग दिनांक 07/06/2026 से सभी PRS काउंटरों तथा IRCTC की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी।

उपरोक्त गाड़ी विशेष किराए पर विशेष ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

हमें लाइक करें और फॉलो करें:

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के साथ अपना वास्तविक पहचान पत्र भी साथ रखें

नए दौर की शुरुआत: दक्षिण गुजरात के उद्योग जगत को मिला अनुभवी नेतृत्व, नवाचार और वैश्विक विस्तार पर रहेगा फोकस

दक्षिण गुजरात का औद्योगिक परिदृश्य हमेशा से देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। टेक्सटाइल, डायमंड, केमिकल, फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों के कारण यह क्षेत्र न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की औद्योगिक शक्ति का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। ऐसे में जब इस क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली व्यापारिक और औद्योगिक संस्था द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) में नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो यह केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि उद्योग जगत की भावी दिशा और विकास की नई संभावनाओं का संकेत भी माना जाता है।

इसी क्रम में वरिष्ठ उद्योगपति अशोक जीरावाला ने एसजीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में और युवा उद्योग प्रतिनिधि रवि राज देसाई ने उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में यह जिम्मेदारी पूर्व अध्यक्ष निखिल मद्रासी द्वारा औपचारिक रूप से सौंपी गई। इस अवसर पर उद्योग, राजनीति, न्यायपालिका और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया।

समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटील, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी, उद्योगपति आनंद देशपांडे, बालाजी वेफर्स के संस्थापक चंदूभाई विरानी, राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया सहित अनेक उद्योगपतियों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। यह उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि एसजीसीसीआई केवल एक व्यापारिक संगठन नहीं, बल्कि दक्षिण गुजरात के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।

पिछले कार्यकाल के दौरान निखिल मद्रासी ने संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में चैंबर ने उद्योगों की समस्याओं को विभिन्न सरकारी मंचों तक पहुंचाने, व्यापारिक प्रदर्शनियों के आयोजन, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और नए निवेश अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। उनके कार्यकाल में संगठन की सक्रियता और प्रभाव दोनों में वृद्धि हुई। दक्षिण गुजरात के उद्योगों की आवाज को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में उनकी भूमिका को उद्योग जगत लंबे समय तक याद रखेगा।

अब जब संगठन की कमान अशोक जीरावाला के हाथों में आई है, तो उद्योग जगत को उनसे काफी उम्मीदें हैं। टेक्सटाइल उद्योग में उनका अनुभव और सक्रियता उन्हें उद्योगों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने वाला नेतृत्व प्रदान करती है। दक्षिण गुजरात विशेष रूप से सूरत का टेक्सटाइल उद्योग देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। लाखों लोगों को रोजगार देने वाला यह क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बदलती तकनीकों के दौर में लगातार नए अवसरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है।

अशोक जीरावाला लंबे समय से बुनकरों और टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं। फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उद्योग के हितों की रक्षा और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। चैंबर से उनका लगभग दो दशक का जुड़ाव संगठन की कार्यप्रणाली और उद्योगों की आवश्यकताओं की गहरी समझ प्रदान करता है। उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावी भूमिका निभाई और विभिन्न सरकारी मंचों पर उद्योग जगत का पक्ष मजबूती से रखा।

उनकी सोच स्पष्ट रूप से भविष्य की ओर केंद्रित है। उनका मानना है कि आने वाले समय में केवल पारंपरिक औद्योगिक मॉडल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। उद्योगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को अपनाना होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में तकनीक ही वह माध्यम है जो उत्पादकता, गुणवत्ता और लागत नियंत्रण में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

इसी प्रकार नए उपाध्यक्ष रवि राज देसाई का चयन भी संगठन के भीतर नई पीढ़ी को नेतृत्व में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कम उम्र में इस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचना उनकी क्षमता, नेतृत्व कौशल और उद्योगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इंजीनियरिंग और प्रबंधन की मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखने वाले रवि राज देसाई आधुनिक औद्योगिक सोच और नवाचार आधारित विकास के समर्थक माने जाते हैं।

विभिन्न औद्योगिक और सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें उद्योगों की बदलती जरूरतों और युवा उद्यमियों की अपेक्षाओं की अच्छी समझ है। उनका नेतृत्व नई पीढ़ी के उद्यमियों को संगठन के साथ जोड़ने और उद्योग जगत में नवाचार आधारित सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वर्तमान समय में स्टार्टअप संस्कृति, तकनीकी नवाचार और वैश्विक बाजारों में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए युवा नेतृत्व की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

नए नेतृत्व की प्राथमिकताओं पर नजर डालें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि संगठन अब पारंपरिक व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ तकनीकी परिवर्तन और वैश्विक विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। टेक्सटाइल, डायमंड, केमिकल और फार्मास्युटिकल जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नई तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने की योजना उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उद्योगों को इन तकनीकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता बन चुका है। उत्पादन प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाना, गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार लाना, लागत को कम करना और वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पाद विकसित करना अब केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है। ऐसे में एसजीसीसीआई की भूमिका उद्योगों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण हो सकती है।

वैश्विक बाजारों से संपर्क मजबूत करना भी नई टीम की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक जुड़ी हुई है। ऐसे में दक्षिण गुजरात के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के अवसरों से जोड़ना क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को नई गति दे सकता है। विदेशी निवेशकों, वैश्विक कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना स्थानीय उद्योगों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है।

युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना भी संगठन के एजेंडे में प्रमुख स्थान रखता है। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में युवा उद्यमी नए विचारों और तकनीकी समाधानों के साथ उद्योग जगत में प्रवेश कर रहे हैं। यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और संस्थागत समर्थन प्राप्त हो तो वे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एसजीसीसीआई की नई टीम इस दिशा में विशेष प्रयास करने की योजना बना रही है ताकि नई पीढ़ी के उद्यमियों को उद्योग जगत की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

दक्षिण गुजरात का औद्योगिक क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरत का टेक्सटाइल और डायमंड उद्योग, भरूच और अंकलेश्वर का केमिकल सेक्टर, वलसाड और नवसारी का औद्योगिक विकास तथा उभरते हुए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र इस पूरे क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं। ऐसे में एसजीसीसीआई का नेतृत्व केवल एक संगठन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव लाखों उद्यमियों, व्यापारियों और कर्मचारियों तक पहुंचता है।

अशोक जीरावाला और रवि राज देसाई की नई टीम से उद्योग जगत को यह उम्मीद है कि वे अनुभव और नवाचार का संतुलन स्थापित करते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एक ओर जहां अनुभवी नेतृत्व उद्योगों की पारंपरिक चुनौतियों को समझता है, वहीं युवा नेतृत्व नई संभावनाओं और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में प्रेरित करता है। यही संतुलन भविष्य में दक्षिण गुजरात के औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने में सहायक बन सकता है।

नए नेतृत्व के साथ एसजीसीसीआई अब ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां तकनीक, नवाचार, वैश्विक संपर्क और युवा भागीदारी विकास के प्रमुख आधार बनने जा रहे हैं। यदि इन प्राथमिकताओं पर प्रभावी ढंग से कार्य किया जाता है, तो दक्षिण गुजरात न केवल भारत बल्कि वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर भी अपनी पहचान को और अधिक मजबूत बनाने में सफल हो सकता है।

दक्षिण कोरिया में नाव दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, भारत में जिम्मेदारी की कमी क्यों है?

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हम स्वदेशी की बातें करके और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके खोखली देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब हमारी देशभक्ति की असली परीक्षा का समय आता है, तो ये पाखंडी देशभक्त पूरी तरह विफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि विदेशों में भी हमारे जैसे पुल गिरते हैं, मॉल में आग लगती है और नावों के पलटने से बच्चे मर जाते हैं। लेकिन हमारे लोग वहां के नेताओं और सत्ताधारियों की तरह दृढ़ चरित्र नहीं दिखा पाते।

भारत में जब कोई दुखद घटना घटती है, तो कुछ दिनों की गहमागहमी के बाद हम उसे भूल जाते हैं। न कोई इस्तीफा देता है, न कोई सत्ता खोता है, न ही कोई सख्त कार्रवाई होती है। भारत में नैतिक आधार पर इस्तीफे की घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन वे अतीत की बात हैं। जब हम आसानी से त्रासदियों और उनके आरोपियों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या एक राष्ट्र के रूप में, एक जनता के रूप में, यही हमारा चरित्र है? हम सभी को इसका जवाब देना होगा।

इसलिए, जब भी ऐसी गंभीर घटनाएं होती हैं और लोगों की मौत होती है, तो कड़ी जांच के आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन कड़ी जांच आखिर होती क्या है? अब समय आ गया है कि भर्ती परीक्षाओं के पेपरों की तरह बार-बार दिए जाने वाले ऐसे कड़े जांच आदेशों की भी समितियों द्वारा कड़ी जांच करनी पड़ेगी। क्योंकि अंत में, इन कड़ी जांचों पर भी पानी फेरना पड़ेगा।

चलिए विदेश की बात करते हैं। 16 अप्रैल 2014 को, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के डैनवॉन हाई स्कूल के 16-17 साल के तीन लड़के-लड़कियां पिकनिक के लिए जेसु द्वीप जा रहे थे। 300 से ज़्यादा छात्र-छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ एमवी सोल नाम की नौका पर सवार हुए। माहौल खुशनुमा था, खूब हंसी-मजाक चल रहा था। नौका सुबह 8:49 बजे रवाना हुई। अचानक नौका ने एक तीखा मोड़ लिया और कुछ ही मिनटों में एक तरफ झुकने लगी और डूबने लगी। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। केबिन में रहने के निर्देश दिए जाने के कारण बच्चों को भागने का मौका नहीं मिला। नौका में कुल 304 लोग सवार थे, जिनमें से 250 छात्र-छात्राएं थे। नौका के समुद्र में डूबने पर पूरे दक्षिण कोरिया में शोक की लहर दौड़ गई।

इन सब का नतीजा क्या निकला? अक्षम कप्तान, जो नाव डुबाने के बाद भाग गया था, को 36 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। बाकी 14 चालक दल के सदस्यों को भी पांच से 30 साल तक की जेल की सजा मिली। नाव चलाने वाली कंपनी का मालिक भाग गया और कुछ दिनों बाद उसका सड़ा हुआ शव मिला। पूरे दक्षिण कोरियाई तटरक्षक बल को भंग कर दिया गया। और सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा मंत्रालय नामक एक बिल्कुल नया मंत्रालय बनाया गया।

नाव दुर्घटना का राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री जंग होंग-वॉन ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए दुर्घटना के 11 दिनों के भीतर इस्तीफा दे दिया। बेशक, दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के पास सबसे अधिक शक्ति होती है। यह नाव दुर्घटना तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे के राजनीतिक करियर के लिए घातक साबित हुई। उन्होंने अपना पद तो नहीं छोड़ा, लेकिन वे सार्वजनिक नजरों से ओझल हो चुके थे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भ्रष्ट शासक सार्वजनिक नजरों से ओझल हो गए हैं। फिर भी हमारे शासक सत्ता नहीं छोड़ते। मेरा भारत महान है।

निर्यात की नई उड़ान: उत्तर प्रदेश ने पार किया दो लाख करोड़ का आंकड़ा, आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ा प्रदेश

उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश के औद्योगिक और व्यापारिक मानचित्र पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और दुनिया के कई हिस्सों में जारी भू-राजनीतिक तनावों के बीच प्रदेश ने निर्यात के क्षेत्र में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने न केवल निवेशकों और उद्योग जगत का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि सही नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचे और उद्योग-अनुकूल वातावरण के बल पर कोई भी राज्य वैश्विक व्यापार में अपनी अलग पहचान बना सकता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का कुल निर्यात पहली बार दो लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार करते हुए 2,01,241 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि प्रदेश की बदलती आर्थिक संरचना, बढ़ती औद्योगिक क्षमता और वैश्विक बाजार में बढ़ते प्रभाव का प्रतीक भी है। इस प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष पांच निर्यातक राज्यों में शामिल हो गया है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस सफलता का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश उन शीर्ष पांच राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। सामान्यतः निर्यात में अग्रणी राज्यों को समुद्री बंदरगाहों का लाभ मिलता है, जिससे माल को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना अपेक्षाकृत आसान और कम लागत वाला होता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत लॉजिस्टिक व्यवस्था, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, माल परिवहन सुविधाओं और औद्योगिक विकास के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश का कुल निर्यात लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपये रहा था। इस वर्ष इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों में सुधार नहीं दर्शाती, बल्कि यह बताती है कि प्रदेश की उत्पादन क्षमता, औद्योगिक निवेश और वैश्विक मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। सरकार द्वारा उद्योगों को दी जा रही सुविधाएं, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास इस सफलता के पीछे महत्वपूर्ण कारक माने जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के निर्यात परिदृश्य में गौतमबुद्धनगर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के आंकड़ों के अनुसार, अकेले गौतमबुद्धनगर जिले से 97,703 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। यह प्रदेश के कुल निर्यात का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के निर्यात इंजन के रूप में उभर चुके हैं।

नोएडा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुएं और विभिन्न विनिर्माण इकाइयों का तेजी से विकास हुआ है। देश और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने यहां निवेश किया है, जिसके कारण यह क्षेत्र निर्यात का प्रमुख केंद्र बन गया है। विशेष रूप से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में हुई वृद्धि ने निर्यात को नई गति प्रदान की है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में नोएडा की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।

गाजियाबाद भी निर्यात के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है। जिले से 18,728 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया है। इंजीनियरिंग उत्पादों, मशीनरी, औद्योगिक उपकरणों और विभिन्न विनिर्माण इकाइयों के कारण गाजियाबाद लंबे समय से औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता और उत्कृष्ट परिवहन सुविधाओं ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कानपुर नगर और मुरादाबाद ने भी अपने पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों की बदौलत निर्यात में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

जेल की सलाखों के पीछे से रची गई 50 लाख की लूट! सूरत पहुंचा मास्टरमाइंड, अब खुल सकते हैं कई बड़े राज

सूरत शहर में अप्रैल महीने में हुई 50 लाख रुपये की सनसनीखेज बैंक लूट की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि इस मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर चल रहे इस कांड के कथित मास्टरमाइंड कुंदन भगत को आखिरकार बिहार की बेउर जेल से सूरत लाया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी आमने-सामने पूछताछ से न केवल इस हाई-प्रोफाइल लूटकांड के कई अनसुलझे पहलुओं से पर्दा उठेगा, बल्कि एक ऐसे संगठित आपराधिक नेटवर्क की परतें भी खुल सकती हैं, जो राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है।

27 अप्रैल को वराछा क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिनदहाड़े हुई लूट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। बैंक में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक उस समय दहशत में आ गए थे, जब हथियारबंद बदमाश अचानक बैंक के भीतर घुस आए। कुछ ही मिनटों में उन्होंने बैंक का माहौल अपने नियंत्रण में ले लिया और कर्मचारियों तथा ग्राहकों को बंधक बनाकर लाखों रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से अंजाम दी गई कि लोगों को संभलने का अवसर तक नहीं मिला।

घटना के बाद सूरत पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई विशेष टीमें गठित कीं। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और अन्य सूचनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस ने शुरुआती चरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान जो जानकारी सामने आई, उसने जांच को नया मोड़ दे दिया। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि पूरी वारदात की योजना किसी स्थानीय गिरोह ने नहीं बल्कि बिहार में जेल में बंद एक अपराधी ने तैयार की थी।

जांच के दौरान सामने आया नाम था कुंदन भगत। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुंदन भगत लंबे समय से संगठित अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है और उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह नवंबर 2025 से बिहार की बेउर जेल में बंद था, लेकिन जेल में रहने के बावजूद उसके आपराधिक नेटवर्क की गतिविधियां जारी थीं। पुलिस को संदेह है कि उसने जेल के भीतर से ही अपने सहयोगियों के माध्यम से पूरी लूट की योजना तैयार की और उसे क्रियान्वित कराया।

सूरत पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपी तक पहुंच बनाना और उसे पूछताछ के लिए गुजरात लाना। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के कई चरणों से गुजरना पड़ा। स्थानीय अदालतों और बिहार की अदालतों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। प्रारंभिक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ पर भी विचार किया गया, लेकिन जांच अधिकारियों का मानना था कि इस तरह के संगठित अपराध में प्रत्यक्ष पूछताछ अधिक प्रभावी साबित हो सकती है। इसके बाद विशेष अनुमति प्राप्त कर पुलिस टीम बिहार पहुंची और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को ट्रांजिट कस्टडी में लेकर सूरत पहुंची।

पुलिस सूत्रों का मानना है कि कुंदन भगत केवल एक सामान्य अपराधी नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का संचालक रहा है। उस पर हथियारों की तस्करी, रंगदारी वसूली, अवैध गतिविधियों में संलिप्तता और कई गंभीर अपराधों के आरोप पहले से दर्ज हैं। बिहार में गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एके-47 राइफल बरामद होने की बात भी जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में दर्ज है। यही कारण है कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां भी उसके आपराधिक नेटवर्क पर नजर बनाए हुए थीं।

जांच में यह भी सामने आया है कि कुंदन भगत कथित रूप से अलग-अलग राज्यों से अपराधियों की भर्ती करता था। इन लोगों को विशेष कोड नेम दिए जाते थे और फिर उन्हें अलग-अलग प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के लिए तैयार किया जाता था। पुलिस को संदेह है कि उसके गिरोह में शामिल कई सदस्य पेशेवर तरीके से काम करते थे और वारदातों को अंजाम देने से पहले विस्तृत रेकी तथा रणनीतिक योजना तैयार की जाती थी।

सूरत बैंक लूट मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने बैंक की गतिविधियों का पहले से अध्ययन किया था। बैंक में नकदी की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों की संख्या और आने-जाने के रास्तों जैसी सूचनाओं का विश्लेषण किया गया था। इसके बाद लूट की योजना बनाई गई। यही वजह है कि अपराधियों ने बेहद कम समय में वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार होने में सफल रहे। मामले की जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। पुलिस के अनुसार, गिरोह की योजना केवल नकदी तक सीमित नहीं थी। बैंक में मौजूद सोने और हीरे के आभूषणों पर भी उनकी नजर थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यदि परिस्थितियां अनुकूल होतीं तो आरोपी बैंक में रखे बहुमूल्य आभूषणों को भी निशाना बना सकते थे। हालांकि घटनास्थल पर बने हालात और समय की कमी के कारण वे केवल नकदी लेकर भाग निकले। अब पुलिस की निगाह इस बात पर केंद्रित है कि लूट की रकम आखिर कहां पहुंची और उसका कितना हिस्सा बरामद किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कुंदन भगत से पूछताछ के दौरान लूट की रकम के वितरण, उसके सहयोगियों की भूमिका और पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। जांच एजेंसियां यह भी जानना चाहती हैं कि क्या इस गिरोह ने देश के अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है या उनकी योजना बना रखी थी। पुलिस के अनुसार, मामले में अभी भी पांच से छह आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश के लिए विभिन्न राज्यों में टीमें सक्रिय हैं। तकनीकी निगरानी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और पूछताछ से फरार आरोपियों के ठिकानों का पता लगाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

सूरत पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करने की तैयारी कर रही है। रिमांड अवधि के दौरान उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस पूछताछ से न केवल बैंक लूट की पूरी साजिश का खुलासा होगा, बल्कि अपराधियों के उस नेटवर्क की भी जानकारी सामने आएगी, जो विभिन्न राज्यों में सक्रिय होकर बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है। यह मामला एक बार फिर यह संकेत देता है कि संगठित अपराध अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ चुका है।

सिमडेगा के बागों से ब्रिटेन तक पहुंची मिठास: आम्रपाली आम ने लिखा झारखंड की कृषि सफलता का नया अध्याय

झारखंड की धरती एक बार फिर अपनी कृषि क्षमता और किसानों की मेहनत के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। सिमडेगा जिले में उगाया गया आम्रपाली आम अब हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ब्रिटेन के बाजारों तक पहुंच चुका है। यह केवल फलों की एक खेप का निर्यात नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की उस बदलती तस्वीर का प्रतीक है जिसमें स्थानीय उत्पाद वैश्विक पहचान प्राप्त कर रहे हैं और किसान आत्मनिर्भरता की नई मिसाल स्थापित कर रहे हैं। सिमडेगा के बागानों में तैयार हुए आम्रपाली आम की पहली व्यावसायिक खेप का ब्रिटेन के लिए रवाना होना झारखंड के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। कुल 1,322 किलोग्राम आम्रपाली आम को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए भेजा गया है। इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि यदि किसानों को उचित मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और निर्यात से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो देश के दूरस्थ क्षेत्रों के कृषि उत्पाद भी वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। यह सफलता अचानक नहीं मिली है। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, बेहतर कृषि प्रबंधन, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों की लगन शामिल है। सिमडेगा के किसानों ने जिस समर्पण के साथ आम्रपाली आम का उत्पादन किया, उसी का परिणाम है कि आज उनका उत्पाद अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। विशेष रूप से यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महिला किसानों की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से यह निर्यात संभव हो सका। एपीडा लंबे समय से भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। संस्था का उद्देश्य किसानों को निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। सिमडेगा के आम्रपाली आम की यह पहली व्यावसायिक खेप इसी दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस उपलब्धि को 'लोकल से ग्लोबल' अभियान का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। उनका मानना है कि भारत के स्थानीय उत्पादों में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की पूरी क्षमता है। जब किसी गांव या जिले का उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचता है, तो उसका लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है।

इस पहल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि आम्रपाली आम किसानों से 42 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए, जो स्थानीय बाजार में मिलने वाले सामान्य मूल्य से अधिक है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। कृषि क्षेत्र में अक्सर किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उचित मूल्य प्राप्त करने की होती है। निर्यात के माध्यम से जब उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचते हैं तो किसानों को बेहतर आय प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ निर्यातोन्मुख खेती को किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हैं। सिमडेगा में उगाए गए ये आम्रपाली आम महिला किसान उत्पादक संगठनों द्वारा तैयार किए गए हैं। यह तथ्य इस सफलता को और अधिक विशेष बनाता है। ग्रामीण भारत में महिलाओं की भूमिका कृषि क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण रही है, लेकिन अब वे केवल खेती तक सीमित नहीं हैं। वे संगठित समूहों के माध्यम से उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। महिला किसान उत्पादक संगठनों की यह सफलता देशभर की महिलाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन सकती है।

इन आमों का उत्पादन 'बिरसा हरित ग्राम योजना' के अंतर्गत किया गया है। यह योजना झारखंड में कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के तहत बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। सिमडेगा में आम्रपाली आम की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि योजनाओं को सही दिशा और प्रभावी क्रियान्वयन मिले तो वे ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आम्रपाली आम स्वयं में एक विशेष किस्म मानी जाती है। इसकी मिठास, आकर्षक रंग, कम रेशेदार गूदा और लंबी शेल्फ लाइफ इसे बाजार में लोकप्रिय बनाती है। उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।